(ख) क्या सरकार को पिछले कुछ महीनों के दौरान बिहार से भुखमरी की वजह से हुई मौतों के संबंध में कोई सूचना मिली है और यदि नहीं, तो क्या सरकार इस संबंध में बिहार में सिंहभूम के आदिवासी क्षेत्रों में कोई जांच करवाने का विचार रखती है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) 5 अगस्त, 1991 के स्टेट्समैन में "कालाहांडी रिपोर्ट सबमिटेड टू पी. एम." शीर्षक से प्रकाशित समाचार की जानकारी सरकार को मिल गई है । उड़ीसा सरकार से मिली रिपोर्ट के अनुसार कालाहांडी जिले में भूखमरी से मौत का कोई मामला घटित नहीं हुआ है।

(ख) जी, नहीं ।

राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम

2289. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये वर्ष 1986-87 में राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किसानों को अच्छे किस्म के बीज उपलब्ध करवाना तथा कृषि उत्पादन में विकास के लिये उन्हें इसके उन्नत तरीकों से अवगत कराना भी शामिल था ;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार द्वारा वर्षवार कुल कितनी राशि व्यय की गयी ;

(घ) क्या यह भी सच है कि वर्तमान में देश में प्रति हैक्टेयर दालों के उत्पादन का औसत विश्व के अनेक दाल उत्पादक देशों के मुकाबले कम हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो फ्रांस, अमरीका, चीन, रूस, तुर्की, ब्राजील, पाकिस्तान, बांगलादेश, हंगरी, केनिया, म्यांमार (बर्मा) आदि देशों में दालों का प्रति हैक्टेयर औसत उत्पादन कितना है तथा वर्ष 1985-86 तथा 1990-91 में देश में दालों का प्रति हैक्टेयर औसत उत्पादन कितना रहा ।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय की गयी राशि इस प्रकार है —

वर्ष	व्यय की गयी राशि
1988-89	567.444 लाख रुपये
1989-90	830.30 लाख रुपये
1990-91	1168.58 लाख रुपये

(घ) जी, हां ।

(ङ) विभिन्न देशों में दलहनों का प्रति हैक्टेयर औसत उत्पादन विवरण में दिया गया है ।

विवरण

कुछ देशों में कुल दलहनों की प्रति हैक्टेयर उपज 1985-89

(कि० ग्रा० प्रति हैक्टेयर)

देश	1985	86	87	88	89
विश्व	774	771	206	808	828
1. केन्या	900	1080	520	607	667

देश	1985	86	87	88	89
2. अमेरिका	1634	1763	1745	1713	1666
3. ब्राजील	475	401	382	486	472
4. बंगलादेश	746	736	717	731	729
5. चीन	1319	1228	1296	1170	1203
6. पाकिस्तान	510	547	517	449	464
7. तुर्की	1038	1124	1052	1037	906
8. हंगरी	2242	2040	1932	2354	2002
9. फ्रांस	4458	3813	4053	4896	4127
10. सोवियत संघ	1460	1180	1541	1379	1526
11. म्यानमार	758	757	806	843	844

स्रोत : खाद्य तथा कृषि संगठन की प्रोडक्शन ईयर बुक 87,88 और 89

	1985–86	86–87	87–88	88–89	89–90	90–91 (एफ)
भारत	547	506	515	598	549	576

(एफ) अन्तिम

Shortage of, hybrid seed

2290. SHRI CHIMANBHAI MEHTA:
SHRI SOM PAL:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is acute shortage of hybrid seeds in India;

(b) whether it is also a fact that nonavailability of such seeds is hampering cultivation of high yielding varieties of several important crops; and

(c) if so, what measure are contemplated to meet the shortage?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): (a) to (c) There is acute shortage of hybrid seed of Sunflower only. In order to meet the shortage of hybrid Sunflower seed, imports have been allowed to supplement the requirements.

कृषि मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र की कम्पनियां

2291. श्री राम अवधेश सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन कार्यरत सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों की संख्या कितनी है और उनके नाम, कार्य-संचालन स्थल, उनके मुख्यालय, कुल पूंजी इक्विटी संबंधी भागीदारी तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके हुए लाभ-हानि संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान इन कम्पनियों के प्रधानों की निजी परिसम्पत्तियों के बारे में जांच करने के लिये सरकार कोई विशेष जांच दल गठित करने का विचार रखती है ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?